

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2172
गुरुवार, 18 दिसम्बर, 2025/27 अग्रहायण, 1947 (शक)

रोजगार पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभाव

2172. डा. विक्रमजीत सिंह साहनी:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने, विशेषकर बड़े पैमाने पर विस्थापन के जोखिम का उल्लेख करने वाली उन हालिया रिपोर्टों के मद्देनजर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के कारण देश में नौकरियों में अत्यधिक कमी आने के संबंध में कोई अध्ययन कराया है या कराने की योजना बना रही है;
- (ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा और समय-सीमा क्या है;
- (ग) क्या सरकार एआई से प्रभावित कर्मचारियों की री-स्किलिंग और उन्हें फिर से तैनात करने के लिए कोई उपाय करने का विचार रखती है;
- (घ) यदि हां, तो ऐसे कार्यक्रमों की प्रकृति क्या है; और
- (ङ) क्या सरकार वर्तमान रोजगार और कौशल योजनाओं के तहत एआई-अनुकूल रोजगार सृजन को एकीकृत करने की योजना बना रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): नैसकॉम की अगस्त 2024 में प्रकाशित "एडवांसिंग इंडियाज एआई स्किल्स" रिपोर्ट के अनुसार, भारत में एआई प्रतिभा के वर्ष 2027 तक 15 प्रतिशत चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से 6 लाख-6.5 लाख पेशेवरों से 12.50 लाख पेशेवरों से अधिक बढ़ने की उम्मीद है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से डेटा साइंस, डेटा क्यूरेशन आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार सृजन होने की संभावना है। अब तक, एआई/बिग डेटा एनालिटिक्स प्रौद्योगिकियों के 3.20 लाख अभ्यर्थियों सहित 8.65 लाख अभ्यर्थियों ने विभिन्न पाठ्यक्रमों में नामांकन/प्रशिक्षण लिया है। इसके अतिरिक्त, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित 10 नई/उभरती प्रौद्योगिकियों में रोजगार के लिए आईटी कर्मियों की री-स्किलिंग/अप-स्किलिंग के लिए 'फ्यूचर स्किल्स प्राइम' कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तहत अब तक 18.56 लाख से अधिक अभ्यर्थी फ्यूचर स्किल्स प्राइम पोर्टल पर जुड़े हैं, जिनमें से 3.37 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने अपना कोर्स पूरा कर लिया है।

इसके अलावा, एमईआईटीवाई द्वारा नासकॉम की साझेदारी से कार्यान्वित, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के लिए उत्कृष्टता केंद्र योजना के तहत, स्टार्टअप्स को विनिर्माण कंपनियों के उपयोग हेतु एआई आधारित टूल और एप्लिकेशन विकसित करने के लिए सहायता दी जाती है। विनिर्माण क्षेत्र में कंपनियों द्वारा ऐसे कई उपाय प्रयोग किए गए हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन (एनईजीडी), एमईआईटीवाई ने अपने साझेदारों के साथ मिलकर स्कूली छात्रों के लिए 'युवाआई: एआई के साथ युवाओं की उन्नति और विकास' नामक एक राष्ट्रीय कार्यक्रम कार्यान्वित किया है जिसका उद्देश्य कक्षा 8वीं से 12वीं तक के स्कूली छात्रों को समावेशी तरीके से एआई तकनीक और सामाजिक कौशल प्रदान करना है। यह कार्यक्रम युवाओं को 8 विषयक क्षेत्रों- कृषि, आरोग्य, शिक्षा, पर्यावरण, परिवहन, ग्रामीण विकास, स्मार्ट सिटी तथा विधि और न्याय में एआई कौशल सीखने और प्रयोग करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।

भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय, राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल चला रहा है, जो निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों की जानकारी, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, रोजगार क्षमता वृद्धि कार्यक्रम आदि सहित करियर से संबंधित सेवाएं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप समाधान है।
